समानता के आधार पर न्यायोचित वेतन-मानों की सिफारिश करने के लिए वर्ष 1974 में न्यायमूर्ति के० सी० पुरी की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति गठित की गयी थी। समिति ने मई 1979 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। औद्योगिक कर्म-चारियों के सम्बन्ध में ही समिति की सिफा-रिशों का आंशिक रूप से क्रियान्वयन किया गया जिन्हें 16-10-81 से लागू करने के आदेश दिए गए हैं। लेकिन खेद है कि गैर-औद्योगिक कर्मचारियों को अभी तक न्याय नहीं मिला है। इस मामले पर मन्त्री महोदय को ध्यान देना चाहिये और उक्त समिति की सभी सिफारिशें तुरन्त लागू की जानी चाहिए।

(iv) SETTING UP OF DIESEL WORKSHOP IN PLACE OF LOCO SHED IN SHORANUR, KERALA.

SHRI K. KUNHAMBU (Cannanore) : The loco shed in Shoranur, Karela, was started as far back as 1896. This shed was started with a work force of 25 and today after 86 years of its existence, it has more than 1000 workers working in it. This loco-shed has played an important role in the development of Shoranur.

Now, with the diesalisation of railway engines having been started, this shed is going to be wound up. The result is that about 700 families will have to vacate their quarters and leave the place.

It is said that some of these workers will be absorbed gradually in traffic, signal, electric and other sections. Some, I understand, will be absorbed in the RPF. Also, there is a proposal to construct a parcel container and a workshop for repairing small wagons and some workers will be absorbed there. But even then a large number of workers will not get any job as there is no arrangement to absorb them. This situation has caused great anxiety among the workers and the people of this area in general, as this will cripple the economic life of this area.

In this situation, it is essential to set up a big diesel workshop in place of the loco shed. This alone will ensure the continued development of this area. Therefore, I earnestly request the Government to set up a diesel workshop in Shoranur.

(v) WASTAGE OF COOKING GAS DUE TO NON-AVAILABILITY OF SUFFICIENT LPG SYLINDERS AT BARAUNI REFINERY IN BIHAR.

श्रीमती माधुरी सिंह (पूर्णियां) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान पूर्णियां क्षेत्र के बरौनी रिफाइनरी की ओर आकृष्ट करना चाहती हूं, जहां पर इस ईंधन की अत्यल्पता एवं कमी के युग में भी जहां एक ओर जनता को विकराल कठिनाइयों तथा अभाव का सामना करना पड़ रहा है, वहीं इस रिफाइनरी में करोड़ों रुपये की कीमत की खाना बनाने की गैस (एल० पी० जी०) को बरबाद किया जा रहा है तथा उसे यूं ही व्यर्थ में फूंक दिया जा रहा है जिसका कारण आज तक इस ओर सरकार का उचित ध्यान न दिया जाना ही कहा जा सकता है क्योंकि गैस सिलेन्डरों की पूर्ति नहीं की जा रही है, जिससे यह गैस बेकार में जला दी जाती है। इस महत्वपूर्ण ईंधन का दुरुपयोग हो रहा है और जिसके प्रयोग से जनता को अभी तक दूर रखा गया है। सरकार को तत्काल युद्ध स्तर पर इस ओर ध्यान देकर इस महत्वपूर्ण विषय को सुल-झाना चाहिये तथा जनता को लाभान्वित करना चाहिये।